नई आर्थिक नीति का अर्थ

अनिल कुमार सिंह[1]

रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ० सी० रंगराजन के अनुसार, ''नई आर्थिक नीति में जुलाई 1991 के बाद से किये गये विभिन्न नीतिगत उपाय और परिवर्तन शामिल हैं। इन सभी उपायों का साझा लक्ष्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को बढ़ाना है। विभिन्न नियन्त्रणों वाले विनिमय तंत्र की चाहे वह निजी क्षेत्र में क्यों न हो बिखर जाती है और प्रतियोगिता का स्तर भी घट जाता है। इन आर्थिक नीति का उद्देश्य से अर्थव्यवस्था में और अधिक प्रतियोगी वातावरण तैयार करना है ताकि प्रणाली की उत्पादकता तथा कुशलता में सुधार हो।''

नब्बे के दशक में जो नई आर्थिक नीति अपनायी गयी थी उसके निम्नलिखित उद्देश्य थे:

- अतीत में प्राप्त लाभों का समायोजन करना।
- अर्थव्यवस्था में विकास की दर को बढ़ाना।
- उत्पादन इकाईयों की कार्यकुशलता एवं उत्पादकता स्तर में सुधार लाना।
- उत्पादन इकाईयों की प्रतिसपर्द्धात्मक क्षमता को बढ़ाना।
- आर्थिक विकास के वास्ते विश्वव्यापी संसाधनों का प्रयोग करना।

नई आर्थिक नीति के मुख्य अंग (Main Components of new economic policy):

- नई औद्योगिक नीति (New Industrial Policy)
- नई व्यापार नीति (New Trade Policy)
- नई राजकोषीय नीति (New Fisical Policy)
- नई मौद्रिक नीति (New Monetary Policy)
- नई निवेश नीति (New Investment Policy)
- वित्त का विश्वव्यापीकरण (Globlizartion of finance)

1. नई औद्योगिक नीति (New Industrial Policy): 1991 के अन्तर्गत बहुआयामी औद्योगिक नीति सुधारों द्वारा भारतीय उद्योग में संरक्षणवाद को समाप्त करके प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का सूत्रपात किया गया। नई औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

- सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा विनियोग के लिए सुरक्षित क्षेत्रों को 17 से कम करके अब केवल 4 कर दिया गया है।
- केवल 6 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी प्रकार की औद्योगिक इकाईयों को लाइसेंस लेने से मुक्त कर दिया गया है।
- MRTP की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है।
- लघु उद्योगों की विनियोग सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रूपये कर दिया है।

[1] शोध छात्र, अर्थशास्त्र विभाग, पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय, सैदपुर, गाजीपुर

- विदेशी पूँजी विनियोग की सीमा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 57 प्रतिशत कर दी गयी है।
- उच्च प्राथमिकता के 34 उद्योगों में 51 प्रतिशत तक पूँजी विनियोग की बिना रोक–टोक के दी जायेगी।
- उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों को तकनीकी समझौते करने के लिए कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

2. नई व्यापार नीति (New Trade Policy): नई आर्थिक नीति में अर्थव्यवस्था के उन्नयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये–

- भारतीय अर्थव्यवस्था को अन्तर्राष्ट्रीय रुप से प्रतियोगी बनाने के लिए सीमा शुल्क तथा टैरिफों को धीरे–धीरे कम किया जा रहा है।
- अर्थव्यवस्था के खुलेपन का विस्तार करने के लिए विदेशी निवेश तथा आधुनिक तकनीक को प्रोत्साहित किया गया है।
- भुगतान सन्तुलन के घाटे को पूरा करने के लिए कई कदम उठाये गये हैं। निर्यातों को प्रोत्साहित किया गया है। विश्व के विदेशी व्यापार में भारत के भाग को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न किये जायेंगे।
- विनिमय दर का समायोजन करने के लिए सरकार ने जुलाई 1991 में रुपये का औसतन 20 प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया। इसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन तथा पूँजी की अन्तर्वाह की गति को तिव्र करना था। निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता कर दी गयी थी।

3. नई राजकोषीय नीति (New Fisical Policy): भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों का एक प्रमुख लक्ष्य राजकोषीय घाटा जो कि 1990–91 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 8.5 प्रतिशत को कम करके 4 प्रतिशत करना है। इसके लिए विभिन्न उपाय किये गये, जैसे– सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण, करों में वृद्धि, सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश व सार्वजनिक क्षेत्र के उत्पादन कीमतों में वृद्धि।

सरकार ने राजा चैलेया समिति के प्रतिवेदन के आधार पर दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषण की जिसमें निम्नलिखित सुधार किये गये हैं– (1) कर प्रणाली को अधिक वैज्ञानिक तथा युक्तिपूर्ण बना दिया गया है। आयकर की अधिकतम दर को 50 प्रतिशत से कम करके 30 प्रतिशत कर दिया गया है। (2) विदेशी कम्पनियों के लाभकर को कम कर दिया गया है। (3) आयात निर्यात कर को 250 प्रतिशत से कम करके 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

4. नई मौद्रिक नीति (New Monetary Policy): सरकार ने मौद्रिक सुधार के लिए नरसिंहम कमेटी की नियुक्ति की थी। इस कमेटी की सिफारिशे निम्नलिखित है। इसके आधार पर सरकार ने महत्त्वपूर्ण वित्तिय सुधार किये हैं। जैसे– व्याज दरों का स्वतंत्र निर्धारण, तरलता अनुपात में कमी इसके तहत सरकार ने कानूनी चल निधि अनुपात को 38.5 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत कर दिया है। इसी तरह से ब्त्र को भी धीरे–धीरे कम किया जा रहा है। इसी तरह बैंकिंग प्रणाली एंव बैंकों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की गयी साथ ही बैंकों की लेखा प्रणाली में भी सुधार किया गया।

5. नई निवेश नीति (New Investment Policy): 1991 की आर्थिक नीति के

अन्तर्गत विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये–

- यदि विदेशी कम्पनियाँ भारत में संयुक्त उद्यमों का पूर्ण स्वामित्व प्रापत करना चाहती है या पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनियाँ स्थापित करना चाहती है तो उन्हें इसके लिए पूर्ण स्वतंत्रता होगी।
- एक अनिवासी भारतीय द्वारा दूसरे अनिवासी भारतीय को किये गये शेयरों के हस्तान्तरण पर से नियंत्रण हटा दिये गये हैं।
- विदेशी निवेशक बाजार कीमतों का इक्विटी का विनिवेश कर सकते हैं। इस प्रकार जो धन प्राप्त होगा उसे अपने देश भेज सकते हैं।
- आधारिक संरचना, जैसे सड़कों, बिजली, संचार आदि के विकास के लिए किये जाने वाले विदेशी निवेश पर कई प्रकार की रियायतें तथा सुविधाएँ की गयी है। बिजली घरों में 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी की अनुमति दी गयी है।
- पूँजीगत खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता का प्रयत्न किया जा रहा है।
- विदेशी निवेश की स्वीकृति के लिए एकल खिड़की व्यवस्था करने के लिए विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की स्थापना की गयी है।
- अनिवासी भारतीयों को निर्यात गृहों, व्यापार गृहों, अस्पतालों, निर्यात प्रेरक इकाईयों, होटलों आदि में 100 प्रतिशत निवेश करने की इजाजत दी गयी है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नई आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है–

(i) उत्पादकता में वृद्धि करना।

(ii) आधुनिक तकनीक का प्रयोग।

(iii) उत्पादन क्षमता का पूर्ण विदोहन।

(iv) राजकोषीय घाटे को कम करना।

(v) कृषि को प्राथमिकता एवं कृषि साख में सुधार।

(vi) रोजगार एवं गरीबी–उन्मूलन कार्यक्रमों का प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन।

(vii) ऊपरी ढाँचे के विकास के लिए उदार ऋण नीति।

(viii) मानव संसाधन विकास करना (जीवन प्रत्याशा, जीवन की गुणवत्ता, शिक्षा का विस्तार, स्वास्थ्य सेवाएँ आदि पर।

सन्दर्भ सूची

- भारत का आर्थिक विकास, लेखक– पी०के० चौबे, प्रकाशन– राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2002
- भारतीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एक अनूठा संकलन, लेखक– राजू सिंह, प्रकाशन, सुमन एस० पब्लिकेशन हाऊस, दिल्ली, 2009
- An Integrated Summary of India 2010, Raju Singh, Publication- Suman S. Publication House, Delhi, 2010
- भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रकाशन– प्रतियोगिता साहित्य सीरीज, 2005
- आर्थिक संवृद्धि एवं नियोजन, लेखक–डॉ० वी०सी० सिन्हा, प्रकाशन– साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रा०लि०, 2008